नईदुनिया

अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से जानकारी देर से देने की बात मानी, ईरान के नौ शहरों पर हवाई हमले

ईरान के जवाबी हमलों में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक के घायल होने की पुष्टि

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका ने स्वीकार किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि घायल हुए 96 प्रतिशत सैनिक उपचार के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उनके अनुसार अधिकांश सैनिकों के सिर में हल्की चोटें आई थीं।

पार्नेल ने यह जानकारी उस समाचार के बाद दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान के साथ संघर्ष में घायल हुए सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी सुरक्षा कारणों से जानबूझकर देर से जारी की गई, ताकि सैनिकों की सुरक्षा प्रभावित न हो। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। ईरान ने सोमवार को उन देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसके जवाब में अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान के नौ शहरों पर हवाई हमले किए। ईरानी श्रम समाचार एजेंसी के अनुसार अबदानान, बंदर अब्बास, बंदर लेंगेह, बुशेहर, चाबहार, केश्म द्वीप, सीरिक, शीराज और कोनारक पर हमले किए गए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है।इस बीच ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी बातचीत की। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुए समझौते को फिर से पटरी पर लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। उधर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने या उतारने वाले मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि उनकी सरकार का सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका में जारी जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार ईरान के साथ युद्ध को लेकर आम नागरिकों का समर्थन लगातार घट रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता बहाल की

संयुक्त सचिव की निगरानी में कार्य करने का निर्देश हटाया गया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के उस हिस्से को हटा दिया, जिसमें बोर्ड को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की निगरानी में कार्य करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस निर्देश को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए इसके विरुद्ध दायर अपीलों का निपटारा कर दिया। इस निर्णय के साथ ही केरल वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता बहाल हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा-6 की प्रारंभिक पंक्ति में पहले ही यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ बोर्ड न्यायालय की अनुमति के बिना कोई बड़ा पूंजीगत व्यय अथवा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करेगा। ऐसे में उसी पैरा की अंतिम पंक्ति में दिए गए संयुक्त सचिव की निगरानी संबंधी निर्देश को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले से लागू अन्य शर्तें प्रभावी रहेंगी। संशोधित आदेश के साथ अपीलों का निस्तारण कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद वक्फ बोर्ड अपने कार्यों का संचालन पूर्व निर्धारित न्यायिक शर्तों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कर सकेगा।

इस सप्ताह कई देशों पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है अमेरिका

अस्थायी 10 प्रतिशत शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद नए निर्णय की संभावना

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह कई देशों पर नए आयात शुल्क लगाने की तैयारी में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका द्वारा लागू किया गया अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। इसके बाद अनेक देशों पर नए आयात शुल्क लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक चरण में लगाए जाने वाले नए आयात शुल्क की दर वर्तमान 10 प्रतिशत शुल्क के आसपास रह सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और प्रशासन इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है।

बताया गया है कि अमेरिकी प्रशासन कुछ अन्य मामलों की भी जांच कर रहा है। इन जांचों का उद्देश्य अधिक आयात शुल्क लगाने के लिए आवश्यक कानूनी आधार तैयार करना है। जांच पूरी होने के बाद शुल्क की दरों में और परिवर्तन किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नए आयात शुल्क किन देशों पर लागू किए जाएंगे और उनकी अंतिम दर क्या होगी। इस संबंध में अमेरिकी प्रशासन की ओर से अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

अस्थायी वैश्विक आयात शुल्क की अवधि समाप्त होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत की निगाहें अमेरिका के अगले निर्णय पर टिकी हैं। यदि नए आयात शुल्क लागू किए जाते हैं तो उनका प्रभाव विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने अभी केवल संभावित निर्णय की ओर संकेत किया है और अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

मैसूरु में कारोबारी ने परिवार की हत्या के बाद दी जान

नईदुनिया ब्यूरो, मैसूरुः कर्नाटक के मैसूरु जिले में मंगलवार को एक अचल संपत्ति कारोबारी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घटना हुंसूर कस्बे के न्यू मारुति लेआउट क्षेत्र में हुई। घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें संपत्ति और कर्ज से संबंधित कई बातें लिखी गई हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 49 वर्षीय हरीश के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर अपनी 36 वर्षीय पत्नी निशिथ तथा 14 वर्ष और आठ वर्ष की दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद घर की पहली मंजिल पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान पुलिस को मृतक का एक पत्र मिला है। इसमें उसने लिखा था कि उसका शव ऊपर वाले कमरे में फंदे से लटका मिलेगा। पत्र में तिजोरी में रखे संपत्ति संबंधी दस्तावेजों, उनकी चाबी रखे जाने के स्थान तथा उन दस्तावेजों को एक नामित व्यक्ति को सौंपने का अनुरोध भी किया गया है।

श्रीलंका में डेंगू का गंभीर प्रकोप

76 हजार से अधिक संक्रमित, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की तलाश में वायुसेना ने शुरू किया अभियान

कोलंबो, एजेंसीः श्रीलंका में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू का लगभग एक दशक का सबसे गंभीर प्रकोप सामने आया है। जनवरी से अब तक 76 हजार 44 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 53 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के साथ अब सेना भी रोकथाम अभियान में सक्रिय हो गई है।

श्रीलंका की वायुसेना मानव रहित विमान की सहायता से मानसून की वर्षा के बाद भवनों की छतों पर जमा पानी की पहचान कर रही है। वहीं सेना और पुलिस के जवान घरों, निर्माण स्थलों तथा विद्यालयों का निरीक्षण कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने में जुटे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जुलाई के पहले दो सप्ताह में 18 हजार से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे पहले जून में डेंगू के 21 हजार 537 मामले दर्ज किए गए थे। बढ़ते संक्रमण के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है।

राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण इकाई के कार्यवाहक महानिदेशक कपिला कन्नंगारा ने कहा कि रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गंभीर मामलों में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 75 प्रतिशत मामले डेंगू विषाणु के डीईएनवी-2 प्रकार से जुड़े हैं, जो तेजी से फैल रहा है और चिंता का कारण बना हुआ है।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार डेंगू का यह गंभीर प्रकोप चक्रवात डिटवाह के बाद सामने आया है। नवंबर के अंत में आए इस चक्रवात को श्रीलंका की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना गया था। इस आपदा से आवश्यक आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण की चुनौती और अधिक बढ़ गई है।

कनाडा के उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाएगा अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, 30 दिन बाद लागू होगा निर्णय

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले अनेक उत्पादों पर 50 प्रतिशत नया आयात शुल्क लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय 30 दिन बाद प्रभावी होगा। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कनाडा अमेरिका के मदिरा, मोटर वाहन तथा दुग्ध उत्पादों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार ऊर्जा, पोटाश तथा पहले से क्षेत्र-विशेष आयात शुल्क के दायरे में आने वाले उत्पादों को इस निर्णय से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पाद भी अब इस नए आयात शुल्क के दायरे में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह निर्णय वर्ष 1930 के आयात शुल्क अधिनियम की धारा-338 के तहत लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार इस प्रावधान का उपयोग करते हुए आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ बातचीत तेज करने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका पहले भी मुक्त व्यापार समझौते का उल्लंघन करते हुए एकतरफा आयात शुल्क लगाता रहा है और कनाडा ने केवल उसका जवाब दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है। वहीं अमेरिकी मदिरा उद्योग ने भी आशंका जताई है कि संभावित जवाबी कार्रवाई का असर दोनों देशों के व्यापार और आतिथ्य क्षेत्र पर पड़ सकता है।

साहिबाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलमार्ग पर यातायात बाधित, 53 रेलगाड़ियां प्रभावित

नईदुनिया ब्यूरो, गाजियाबादः गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में मंगलवार तड़के लगभग 2:36 बजे कोयले से लदी एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के कारण व्यस्त गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलमार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ और कुल 53 रेलगाड़ियां प्रभावित हुईं। घटना में किसी के हताहत होने अथवा घायल होने की सूचना नहीं है। डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण कोयला पटरियों पर फैल गया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। इसके बाद लंबी दूरी की 24 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें दिल्ली-नई दिल्ली मार्ग से संचालित किया गया। घटना के कारण कुल 16 यात्री रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया गया, जबकि पांच यात्री रेल सेवाओं को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद मंडल तथा उत्तर मध्य रेलवे के माध्यम से आनंद विहार की ओर जाने वाली आठ रेलगाड़ियों के संचालन में भी परिवर्तन किया गया। रेल अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना से कुल 53 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। दुर्घटना के बाद रेल परिचालन को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, दस लोग गिरफ्तार

बेंगलुरु में अधिकारियों से मारपीट, हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरुः बेंगलुरु में मंगलवार को फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने गई ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण की टीम पर कथित रूप से हमला कर दिया गया। शिवाजी नगर क्षेत्र में हुई इस घटना में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई।

पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार मुख्य आरोपी बसवराज पुडुकोटे की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं। जानकारी के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण की टीम शिवाजी नगर क्षेत्र में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोग कथित रूप से आक्रामक हो गए और उन्होंने अधिकारियों पर हमला कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने सहायक कार्यपालन अभियंता गौतम तथा अन्य अधिकारियों को सड़क पर घसीटकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान एक अन्य अधिकारी रुचिता पर भी कथित रूप से तीक्ष्ण मिर्चयुक्त छिड़काव किया गया, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

स्पेशल खबर दूर के पुरुष रिश्तेदारों को गोद लेने की अनुमति, महिलाओं को अब भी नहीं मिलेगा सम्राट बनने का अधिकार

जापान ने बदले शाही उत्तराधिकार से जुड़े नियम

टोक्यो, एजेंसीः जापान की संसद ने शाही परिवार के उत्तराधिकार से जुड़े कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब शाही परिवार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के दूर के पुरुष रिश्तेदारों को गोद लेकर दोबारा शाही परिवार में शामिल कर सकेगा। इसके साथ ही शाही परिवार की महिलाएं किसी सामान्य नागरिक से विवाह करने के बाद भी अपना शाही दर्जा और आधिकारिक दायित्व नहीं खोएंगी। हालांकि, कानून में यह व्यवस्था यथावत रखी गई है कि केवल पुरुष ही सम्राट बन सकते हैं। वर्तमान सम्राट नारुहितो की एकमात्र पुत्री राजकुमारी आइको लोकप्रिय होने के बावजूद उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगी। वर्तमान में शाही परिवार में सिंहासन के केवल तीन उत्तराधिकारी हैं। इनमें सम्राट के छोटे भाई राजकुमार फुमिहितो, उनके पुत्र राजकुमार हिसाहितो तथा 90 वर्षीय राजकुमार हिताची शामिल हैं। पुरुष उत्तराधिकारियों की सीमित संख्या को देखते हुए भविष्य में उत्तराधिकार संकट की आशंका व्यक्त की जा रही है।

सरकार के सामने महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार देने अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शाही परिवार से अलग किए गए पुराने शाही वंश के पुरुष सदस्यों को पुनः शामिल करने के दो विकल्प थे। सरकार ने दूसरा विकल्प चुना। इसके तहत पूर्व की 11 शाही शाखाओं के 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष वंशजों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लेकर फिर से शाही परिवार में शामिल किया जा सकेगा।

नए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि शाही परिवार की महिला सदस्य यदि किसी सामान्य नागरिक से विवाह करती हैं तो उन्हें अब शाही परिवार नहीं छोड़ना होगा। पहले ऐसे विवाह के बाद महिलाओं का शाही दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता था।

जापान के इतिहास में अब तक आठ महिलाएं महारानी बन चुकी हैं, किंतु वे अपने बच्चों को उत्तराधिकारी नहीं बना सकीं। वर्ष 1889 के मेइजी संविधान तथा वर्ष 1947 के शाही परिवार कानून में पुरुष उत्तराधिकार की व्यवस्था को बनाए रखा गया, जो आज भी प्रभावी है। इसी कारण वर्तमान संशोधन के बावजूद महिलाओं को सम्राट बनने अथवा उनकी संतान को उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं दिया गया है।